IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

स्थानीय स्वशासन और बदलती ग्रामीण शक्ति संरचना

हरिनन्दन कुशवाहा सीनियर रिसर्च फेलो समाजशास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ

सार संक्षेप

प्रारम्भ से ही ग्राम एक समुदाय में संगठित रहा है अतः ग्रामीण संरचना प्रारम्भ से सामुदायिक आधार पर खड़ी रही है। परम्परागत ग्रामीण समाज में जाति प्रथा अत्यन्त कठोर थी जाति समितियाँ एवं जाति पंचायतें अत्यधिक शक्तिशाली थीं और जाति ही व्यक्तियों की गतिशीलता के लिए अवसरों और प्रस्थिति का निर्धारण करती थी यहाँ तक कि भू-स्वामित्व और शक्ति संरचना भी जाति आधार पर चलती थी। परम्परागत शक्ति संरचना में शान्ति व्यवस्था के प्रमुख आयाम जमींदारी प्रथा जाति प्रथा और ग्राम/जाति पंचायत थे। ग्रामीण अपनी सामाजिक आर्थिक और अन्य समस्याएं या तो जमींदार या अपनी जाति के मुखिया को या गाँव की पंचायत को बताते थे। कुछ क्षेत्रों में परम्परागत शक्ति संरचना सामन्तवादी भी थी। भूस्वामित्व तथा उनकी आर्थिक प्रस्थिति गाँव में जागीरदारों और जमींदारों की शक्ति के मूल स्त्रोत थे। स्वतन्त्रता के पश्चात् जागीरदारी व जमींदारी प्रथाएं समाप्त कर दी गईं और अनेक भूमि सुधार लागू कर दिये गये जिसने परम्परागत शक्ति संरचना को कमजोर कर दिया और नवीन शक्ति संरचना को जन्म दिया। आनुवंशिक और जाति मुखियाओं के स्थान पर राजनैतिक पृष्ठभूमि के चुने हुए लोग नेता बन गये। नेतृत्व में व्यक्तिगण गुण न कि जाति मुख्य कारक बन गये हैं। 73वें संविधान संशोधन के उपरान्त नवीन पंचायती राज व्यवस्था में सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के हजारों प्रतिनिधियों को भी चुनाव में जीत मिली है। ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन हुआ है और नेतृत्व की नयी पौध उगी है। प्रस्तुत शोधपत्र में 73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज व्यवस्था में हुए सुधारों के फलस्वरूप ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन की प्रकृति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में स्थिति एक ग्राम पंचायत का उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से चयन कर उस ग्राम पंचायत में निवास करने वाले वयस्क ग्रामीणों का प्रतिदर्श के आधार पर चयन कर उनकी सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक प्रस्थिति में परिवर्तन की प्रस्थिति में परिवर्तन की प्रकृति का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि नवीन पंचायतीराज व्यवस्था के फलस्वरूप ग्रामीण शक्ति संरचना में निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ है नये राजनैतिक गुट बने हैं शक्ति सत्ता और नेतृत्व के प्रतिमान में पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के बाद एक बदलाव आया है।

मुख्य शब्द – लोकतन्त्र ग्रामीण पंचायती राज शक्ति संरचना नेतृत्व ।

प्रस्तावना

लोकतन्त्र एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्येक व्यक्ति (चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, रंग या पहचान से सम्बद्ध हो) को राजनीति समूह या राष्ट्र राज्य के मामलों में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। लोकतान्त्रिक मूल्यों के चलन एवं राजनैतिक स्वतन्त्रता से सभी व्यक्तियों को यह अवसर प्राप्त हुआ है कि वे अपनी पहचान, स्थिति. प्रतिबद्धता, और इच्छाओं में निहित हितों और मूल्योंमुख चेतना और अचेतना के चारों ओर रहकर स्वयं का विकास कर सकें। राजनैतिक स्वतन्त्रता ने सामन्ती जमीदारी प्रथा, जागीरदारी और राजाओं के राज्यों का उन्मूलन करके भारतीय समाज की संरचना और इसकी अधिकार प्रणाली में भारी परिवर्तन करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसने भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक एवं सामाजिक आधार में क्रान्ति लाने का कार्य किया है (आहुजा, 2011:23)।

भारत मूलतः गाँवों का देश है जहाँ 6 लाख से भी अधिक गाँव है जिनका जीवन स्तर एक-दूसरे से भिन्न है और कई जगहों पर कुछ समानताएँ भी पायी जाती हैं। ग्रामीण समुदाय के अन्तर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केन्द्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं (मेरिल एण्ड एलरिज, 1949)। ग्रामीण समाज अपेक्षाकृत स्थिर समाज होते हैं। उनमें सापेक्ष रूप से गतिशीलता का अभाव होता है। ग्रामीण समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसी में व्यक्ति निवास करते हैं। उनका मुख्य पेशा कृषि होता है। समुदाय में उनका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। ग्रामीण समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है (मुकर्जी, 2006:33)। 'ग्राम या गाँव' मानव के सामूहिक जीवन का प्रथम पालना माना गया है। मानव समाज एवं सभ्यता हजारों वर्षों सें ग्रामीण ही रही है। ''पुरातन ग्राम केवल आर्थिक एवं प्रशासनिक ईकाई ही नहीं थे बल्कि वे सहयोगिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केन्द्र रहे हैं। उनके पास अपने त्यौहार, पर्व, लोकगीत, नृत्य, खेल एवं मेले है, जिन्होंने ग्रामीणजन को जीवन दिया और उनके उत्साह को बनाए रखा'' (लवानियाँ व जैन, 1987)। इन टोलियों के कारण मनुष्य के मस्तिष्क में संगठन और सहयोग की भावना को जन्म दिया होगा, जो आगे चलकर नव-पाषाण काल में ग्रामों के रूप में विकसित हो गयी (विद्यालंकार, 1965)।

प्राचीन काल से ही भारत के ग्राम शासन व्यवस्था की मूल एवं प्राथमिक इकाई रहे हैं। यह इकाई स्वावलम्बी ग्राम स्वशासन प्रणाली थी (ऋग्वेद, 1:114)। वैदिक युग में ग्राम-शासन-व्यवस्था का अधिक महत्व था। हर-एक गाँव की शासन-व्यवस्था खुद में 'प्रजातन्त्र' की एक छोटी इकाई मानी जाती थी। इस व्यवस्था में केन्द्रीय सत्ता अधिक हस्तक्षेप नहीं करती थी, जिसके फलस्वरूप ग्राम्य जीवन के प्रत्येक सार्वजनिक पहलू, जैसे-सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक, इसी स्वशासन प्रणाली से संचालित होते थे। एक ग्राम में अनेक कुल होते थे। सम्भवतः यह मुखिया कोई और नहीं बल्कि इनके ग्राम का नेता, जिसे दूसरे शब्दों में 'ग्रामणी' कहा जा सकता है, रहा होगा (अग्रवाल, 1971:117)। महाजनपद काल में ग्राम के शासक को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे ग्रामभोजक, ग्रामणी या ग्रामिक। ग्राम सम्बन्धी सभी मामलों को निपटाने का कार्य ग्रामभोजक के ऊपर था। गाँव वालों के लिए उसकी आज्ञाओं को मानना अनिवार्य होता था, फिर भी, ग्रामभोजक स्वेच्छाचारी नहीं होता था, क्योंकि उसकी स्वेच्छाचारिता के विरूद्ध राजा के पास अपील की जा सकती थी। यह व्यवस्था सल्तनत काल के प्रारम्भ तक बनी रही, लेकिन सल्तनत कालीन राजाओं की स्वेच्छाचारिता एवं केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था ने ग्राम पंचायतों के अधिकार सीमित कर दिये (सरकार, 1958)। मुगल शासन के पतन और ब्रिटिश साम्राज्य के शक्तिशाली होने बीच पंचायतों के स्वरूप में परिवर्तन आया और कई स्थानों में मजबूत हूई, जो कहीं पर कमजोर (टिंकर, 1999)। अंग्रेजी शासन के आरम्भिक दौर में भारतीय ग्रामीण शासन व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया गया और महालवाड़ी, रैय्यतवाड़ी, जमींदारी, ताल्लुकादारी आदि व्यवस्था को जन्म देकर गाँव की प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त कर उन्हें नगरों से जोड़ दिया गया। यद्यपि इस काल में पंचायतीराज व्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के प्रयास भी किये गये। भारत के नये संविधान के मूल प्रारूप में भी पंचायतों का प्रावधान नहीं था। बल्कि संविधान निर्माताओं ने पंचायतों की वैचारिक अवधारणा के रूप में ही 'ग्राम गणतन्त्र' (विलेज रिपब्लिक) की परिकल्पना पर बल दिया था। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायत व्यवस्था का निम्नवत् उल्लेख किया गया है- 'राज्य ग्राम

पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।'

सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा के असफल होने के बाद पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की सिफारिश करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, यथा (1) ग्राम या नगर पंचायत (2) तहसील पंचायत और (3) जिला पंचायत को स्थापित करने की सिफारिश की। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में कई कमियाँ उत्पन्न हो गयीं, जिन्हें दूर करने के लिए 1977 में अशोक सिंधवी समिति (1986) आदि समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 73वें संविधान संशोधन के रूप में 23 अप्रैल, 1993 से नवीन पंचायती राज सम्पूर्ण देश में लागू हुआ।

आन्द्रे बेतेई (1966:180) ने अपने अध्ययन में यह दर्शाया है कि शक्ति काफी हद तक वर्ग से अतीत की अपेक्षा मुक्त हो गई है। शक्ति अर्जन में भू-स्वामित्व अब निर्णायक कारण नहीं है। इकबाल नारायन तथा माथुर (1969) ने राजस्थान के अपने एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि उच्च वर्ग आज भी नेतृत्व पर एकाधिकार जारी रखे हुए है। लेकिन छोटी आयु समूह का नया नेतृत्व भी गाँव के स्तर पर उदित हुआ है। सिरसीकर (1970), राम रेड्डी (1970), ईश्वरन (1970), योगेश अटल (1971), इनामदार (1971), कैराम (1972) आदि ने भी ग्रामीण नेतृत्व अवस्था में परिवर्तन के स्वभाव पर प्रभाव का अध्ययन किया है।

योगेन्द्र सिंह (1994:22) ने राजनैतिक स्वतंत्रता के महत्व को इंगित करते हुए कहा है कि राजनैतिक स्वतंत्रता से एक ऐसे नवीन वर्ग का उदय हुआ है, जो स्वतंत्रता पूर्व के मध्यम वर्ग की विशेषताओं से सर्वथा भिन्न है। इस वर्ग का कहीं अधिक विस्तृत सामाजिक आधार है जो निम्न और मध्यम जातियों और समाज के ऐसे स्तरों से ही सम्बद्ध है। अनेक जातियों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या अपनी स्थिति को सुधारने के लिए राजनीति का सहारा लिया है। रजनी कोठारी (1970) ने अपने अध्ययनों में यह स्पष्ट किया है कि कुछ मध्यम और निम्न जातियों एवं आर्थिक दृष्टि से पतित समुदायों ने संगठित रूप से राजनीति का प्रयोग कर राजनीतिक शक्ति, जाति एकता, और आखिरकार समाज में उच्च स्थिति को प्राप्त किया है।

पंचायती राज व्यवस्था में उभरे नये नेतृत्व में एक प्रमुख परिवर्तन यह है कि आज किसी विशिष्ट व्यक्ति या परम्परागत नेता में ही गाँव/वार्ड की सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित नहीं होती बल्कि जीवन के प्रत्येक विशिष्ट पक्ष तथा विशिष्ट कार्यों से सम्बद्ध पृथक-पृथक व्यक्तियों को नेता के रूप में मान्यता दी जाने लगी है। अब ग्रामीण नेतृत्व मुख्यतः उन व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित होने लगा है जो मध्यम वर्ग के हैं (काला, 2009)। ग्राम स्तर पर पंचायतों के चुनाव अक्सर एक-दूसरे के वोट काटने पर आधारित होकर लड़े जाते हैं। अब बहुत बड़ी संख्या में निर्बल जातियाँ वोट-शक्ति रखती हैं, अतः वे परम्परागत प्रभु-जाति को चुनौती देती हैं। प्रबल जातियाँ तथा उच्चता प्राप्त जातियाँ अक्सर क्षेत्र के प्रमुख राजनैतिक दलों से बँधी होती हैं और दलीय संगठन के माध्यम से ही उध्व गतिशीलता होती रहती हैं। इस प्रकार एक ओर जाति केवल बाह्य राजनैतिक समर्थन आधार खो देती हैं और दूसरी ओर यह राजनीति को अत्यधिक प्रभावित करती हैं (आहूजा, 2011:66)।

एक सशक्त पंचायती राज व्यवस्था में न केवल विकास की गति तेज होती है, बल्कि संगठनों एवं संस्थाओं के लिए अनुकूल वातारण मिलता है। चुनाव में सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के हजारों प्रतिनिधियों को भी चुनाव में जीत मिली है, पर इसके बाद भी उनकी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि पद ग्रहण करने के बाद वास्तविक चुनौतियों से उनका सामना होता है। उन्होंने अपने बल पर अपनी जमीन तलाशनें का काम शुरू भी कर दिया है। शक्ति, सत्ता और नेतृत्व के प्रतिमान में पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के बाद एक बदलाव आया है। इन बदली हुई परिस्थितियों के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन की झलक दिखाई दे रही है। साथ ही

पंचायती राज व्यवस्था नें ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसी समस्याओं को जन्म दिया है जो ग्रामीण जीवन के विघटन के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ कारणों से इस व्यवस्था ने गाँवों में व्याप्त जातिवाद, दलबंदी की भावना, अकुशल राजनैतिक नेतृत्व, भ्रष्टाचार व निजी स्वार्थों में टकराव की प्रक्रिया आदि को बढ़ाया है। इसकी वजह से पंचायती राज संस्थाएँ एक टिकाऊ व जवाबदेह जन निकाय का दर्जा प्राप्त नहीं कर पायी हैं। अतः आवश्यकता है कि इन कारणों का पता लगाया जाए। प्रस्तुत शोधपत्र में ''स्थानीय स्वशासन एवं बदलती ग्रामीण शक्ति संरचना'' शीर्षक के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित एक ग्राम पंचायत की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना में परिवर्तन की प्रवृत्ति का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं:-

भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना का अध्ययन करना।

ग्रामीण शक्ति संरचना में जातीय वर्गों के प्रभाव का अध्ययन करना।

ग्रामीण शक्ति संरचना में पंचायतीराज व्यवस्था की भूमिका का विवेचन करना।

चयनित ग्राम पंचायत की शक्ति संरचना एवं उसमें परिवर्तन की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।

शोध प्रश्न

संबन्धित साहित्य से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित शोध सम्बन्धी प्रश्नों को उठाया गया है:-

73वें संविधान संशोधन लागू होने के पश्चात् नवीन पंचायती राज व्यवस्था के फलस्वरूप ग्रामीण शक्ति संरचना में क्या परिवर्तन आया है?

क्या आज भी बड़े भूमिधर एवं राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवारों का ही स्थानीय शक्ति संरचना पर आधिपत्य है?

पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के पश्चात् क्या वंचित वर्ग के लोगों में राजनीतिक एवं नेतृत्व की चेतना आई है?

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति विश्लेषणात्मक है, जिसमें वर्णनात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के बहलोलपुर ग्राम पंचायत का मिश्रित आबादी के आधार पर उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से चयन कर वहाँ के 120 परिवारों का दैव निदर्शन विधि से चयन किया गया है तथा प्रत्येक परिवार से 01 वयस्क सदस्य का आकस्मिक विधि से चयनकर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दशाओं से सम्बन्धित आँकड़ों का संकलन किया गया है। अध्ययन के उद्देश्यों एवं शोध प्रश्नों के आधार पर संकलित आँकड़ों का विश्लेषण कर स्थानीय स्वशासन एवं बदलती ग्रामीण शक्ति संरचना के मध्य सह-सम्बन्धों का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

वैयक्तिक परिवेश- तालिका सं0 1 में उत्तरदाताओं के वैयक्तिक परिवेश को प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि 86.67% उत्तरदाता हिन्दू एवं 13.33% उत्तरदाता मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। वहीं 39.17% उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के, 35% उत्तरदाता अनुसूचित जाति के तथा 25.83% उत्तरदाता सामान्य वर्ग में हैं। शैक्षिक स्थिति के अनुसार 44.17% उत्तरदाताओं ने हाईस्कूल/इंटरमीडिएट तक, 23.33% उत्तरदाताओं ने प्राइमरी/जूनियर हाईस्कूल तक तथा 19.17% उत्तरदाताओं ने स्नातक या उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त की है, जबकि 13.33% उत्तरदाताओं ने किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त की है।

तालिका सं0 1: उत्तरदाताओं का वैयक्तिक परिवेश

धर्म	हिन्दू	मुस्लिम		
संख्या (प्रतिशत)	104 (86.67)	16 (13.33)		
सामाजिक वर्ग	सामान्य वर्ग	अ॰पि॰व॰	अनु॰ जाति	
संख्या (प्रतिशत)	31 (25.83)	47 (39.17)	42 (35.00)	
शैक्षिक स्तर	निरक्षर/साक्षर	प्राइमरी/जूनियर हाईस्कूल	हाईस्कूल/इंटरमीडिएट	स्नातक/ परास्नातक
संख्या (प्रतिशत)	16 (13.33)	28 (23.33)	53 (44.17)	23 (19.17)

परिवारिक स्वरूप -तालिका सं0 2 में उत्तरदाताओं के पारिवारिक स्वरूप को प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि 57.5% उत्तरदाताओं के पारिवार की प्रकृति संयुक्त एवं 22.5% उत्तरदाताओं के परिवार की प्रकृति एकाकी है। वहीं परिवार के प्रमुख व्यवसाय के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण देखा जाय, तो स्पष्ट होता है कि 99.5% उत्तरदाताओं के परिवार का प्रमुख व्यवसाय कृषि या मजदूरी है, जबकि 7.5% उत्तरदाताओं के परिवार का प्रमुख व्यवसाय नौकरी एवं 3.33% उत्तरदाताओं के परिवार का प्रमुख व्यवसाय परम्परागत/घरेलू स्वरोजगार है।

तालिका सं0 2: उत्तरदाताओं का पारिवारिक परिवेश

परिवार की प्रकृति	एकाकी	संयुक्त		
संख्या (प्रतिशत)	51 (42.50)	69 (57.50)		
व्यवसाय	कृषि/ मजदूरी	व्यापार	नौकरी	घरेलू व्यवसाय
संख्या (प्रतिशत)	99 (82.50)	9 (7.50)	4 (3.33)	8 (6.67)
मासिक आय (ह॰ रु॰ में)	2 से कम	2 से 5	5 से 10	10 से 20	20 से अधिक
संख्या (प्रतिशत)	23 (19.17)	29 (24.17)	33 (27.50)	27 (22. 50)	8 (6.67)
परिवार में सदस्य	3-4	5-6	7-8	9-10
संख्या (प्रतिशत)	17 (14. 17)	37 (30.83)	52 (43.33)	14 (11.67)

वहीं 27.5% उत्तरदाताओं के परिवार की मासिक आय रू0 5 से 10 हजार के मध्य है, जबकि 24.17% उत्तरदाताओं के परिवार की मासिक आय रू0 2 से 5 हजार, 22.5% उत्तरदाताओं के परिवार की मासिक आय रू0 10 से 20 हजार, 19.17% उत्तरदाताओं के परिवार की मासिक आय रू0 2 से कम तथा 6.67% उत्तरदाताओं के पारिवार की मासिक आय रू0 20 से अधिक है।

परिवार में सदस्यों की संख्या के अनुसार उत्तरदाताओं की स्थिति का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि 43.33%उत्तरदाताओं के परिवार में सदस्यों की संख्या 7 से 8 है। इसके उपरान्त 30.83% उत्तरदाताओं के परिवार में सदस्यों की संख्या 5 से 6, 14.17% उत्तरदाताओं के परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 तथा 11.67% उत्तरदाताओं के परिवार में सदस्यों की संख्या 9 से 10 है।

राजनीतिक सहभागिता की स्थिति -राजनीतिक सहभागिता में परिवर्तन की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए उत्तरदाताओं से पंचायत चुनाव के किसी भी स्तर में प्रचार, मतदान एवं उम्मीदवारी में भाग लेने की वर्तमान एवं 10 वर्ष पूर्व की स्थिति में सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन कर उनका विश्लेषण निम्नवत् किया गया है -

चित्र सं0 1 में उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता में परिवर्तन की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 40% उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता की स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है, जबकि 32.5% उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता की स्थिति में सामान्य तथा 27.5% उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता की स्थिति में बहुत कम परिवर्तन हुआ है।

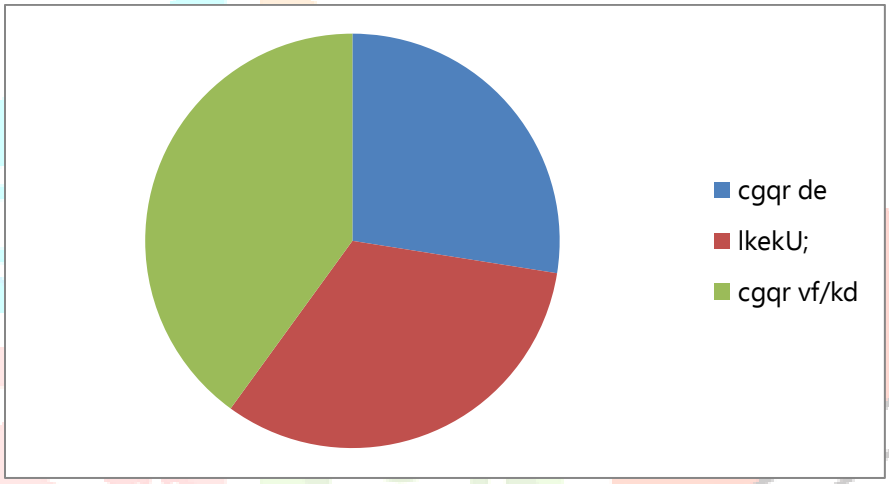

चित्र सं0 1: उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता की स्थिति में परिवर्तन

तालिका सं0 3 में उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता में परिवर्तन की सामाजिक वर्गवार स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के 45.25% उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जबकि इस सामाजिक वर्ग के 38.1% उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता में सामान्य वृद्धि तथा 18.67% उत्तरदाताओं में बहुत कम वृद्धि हुई है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के 44.68% उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता में सामान्य, 29.79% उत्तरदाताओं में बहुत अधिक तथा 25.53% उत्तरदाताओं में बहुत कम वृद्धि हुई है। इसके विपरीत सामान्य वर्ग के 45.16% उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता में बहुत कम, 35.48% उत्तरदाताओं में सामान्य तथा 19.35% उत्तरदाताओं में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

तालिका सं0 3: सामाजिक वर्गवार उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता में परिवर्तन की प्रवृत्ति

परिवर्तन की स्थिति	आयु वर्गवार उत्तरदाताओं का विवरण					
	अनु॰ जाति		अ॰पि॰व॰		सामान्य	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
बहुत कम	7	16-67	12	25-53	14	45-16
सामान्य	16	38-10	21	44-68	11	35-48
बहुत अधिक	19	45-24	14	29-79	6	19-35
योग	**42**	**100-00**	**47**	**100-00**	**31**	**100-00**

तालिका सं0 4: सामाजिक वर्गवार उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता में परिवर्तन की प्रवृत्ति में अन्तर की सार्थकता

सामाजिक वर्ग	राजनीतिक सहभागिता में परिवर्तन की प्रवृत्ति						
	बहुत कम		सामान्य		बहुत अधिक		योग
	प्राप्त	अनुमानित	प्राप्त	अनुमानित	प्राप्त	अनुमानित	
अनु॰ जाति	7	11-55	16	16-80	19	13-65	**42**
अ॰पि॰व॰	12	12-93	21	18-80	14	15-28	**47**
सामान्य	14	8-53	11	12-40	6	10-08	**31**
कुल	**33**	**33**	**48**	**48**	**39**	**39**	**120**

तलिका सं0 4 से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता में परिवर्तन की प्रवृत्ति में सामाजिक वर्गवार स्थिति में अन्तर है। इस अन्तर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए कई-वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

काई-वर्ग का प्राप्त मान = 9.680

स्वतन्त्रता अंश (df) = (3-1) × (3-1) = 2 × 2 = 4

सम्भाव्यता स्तर = 0.05

स्वतन्त्रता अंश 4 एवं सम्भाव्यता स्तर 0.05 पर तालिका काई-वर्ग = 9.488

उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता में परिवर्तन की प्रवृत्ति में सामाजिक वर्गवार स्थिति का आगणित काई-वर्ग मान (9.68) स्वतन्त्रता अंश 4 एवं सम्भाव्यता स्तर 0.05 पर तालिका काई-वर्ग (9.488) से अधिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक वर्गवार उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता में परिवर्तन की प्रवृत्ति में सार्थक अन्तर है।

ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन की प्रवृत्ति -

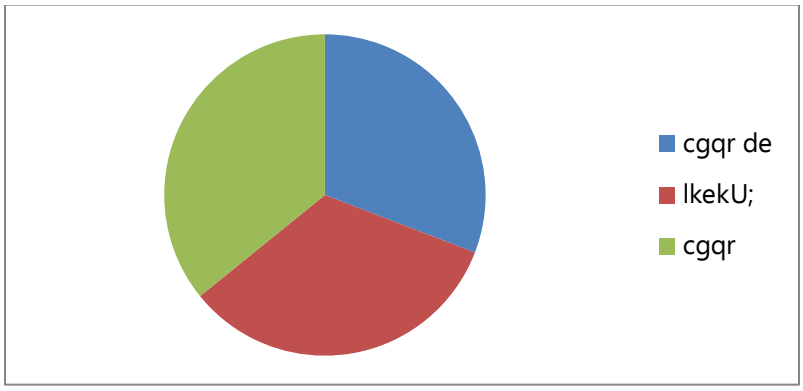

चित्र सं0 2: ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन

तालिका सं0 5 में दर्शित ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की राय का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के 45.24% उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण शक्ति संरचना में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है, जबकि इस वर्ग के 35.71% उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण शक्ति संरचना के सामान्य तथा 19.05% उत्तरदाताओं के अनुसार बहुत कम परिवर्तन हुआ है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के 38.3% उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण शक्ति संरचना में बहुत अधिक, 34.04% उत्तरदाताओं के अनुसार सामान्य तथा 27.66% उत्तरदाताओं के अनुसार बहुत कम परिवर्तन हुआ है। इसके विपरीत सामान्य वर्ग के 51.61% उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण शक्ति संरचना में बहुत कम, 29.03% उत्तरदाताओं के अनुसार सामान्य तथा 19.35% उत्तरदाताओं के अनुसार बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है।

तालिका सं0 5: ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन के बारे में उत्तरदाताओं की सामाजिक वर्गवार राय

परिवर्तन की स्थिति	सामाजिक वर्गवार उत्तरदाताओं का विवरण					
	अनु॰ जाति		अ॰पि॰व॰		सामान्य	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
बहुत कम	8	19.05	13	27.66	16	51.61
सामान्य	15	35.71	16	34.04	9	29.03
बहुत अधिक	19	45.24	18	38.30	6	19.35
योग	**42**	**100.00**	**47**	**100.00**	**31**	**100.00**

काई-वर्ग का प्राप्त मान = 10.103*

तालिका सं0 5 से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण शक्ति संरचना में बहुत अधिक परिवर्तन होना मानने वालों में सबसे अधिक उत्तरदाता अनु0 जाति (19.35%) से हैं। इसके विपरीत बहुत कम परिवर्तन होना मानने वाले उत्तरदाताओं में सबसे अधिक उत्तरदाता सामान्य वर्ग (51.61%) से तथा सबसे कम उत्तरदाता अनुसूचित जाति (19.05%) के हैं। इस अन्तर का आगणित काई-वर्ग मान 10.103 है, जो स्वतन्त्रता अंश 4 एवं सम्भाव्यता स्तर 0.05 पर सारिणी काई-वर्ग मान (9.488) से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की राय में सामाजिक वर्गवार सार्थक अन्तर है।

तालिका सं0 6: ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन के बारे उत्तरदाताओं की आर्थिक वर्गवार राय

परिवर्तन की स्थिति	आर्थिक वर्गवार उत्तरदाताओं का विवरण					
	निम्न		मध्यम		उच्च	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
बहुत कम	11	21.15	10	28.57	16	48.48
सामान्य	16	30.77	14	40.00	10	30.30
बहुत अधिक	25	48.08	11	31.43	7	21.21
योग	**52**	**100.00**	**35**	**100.00**	**33**	**100.00**

काई वर्ग का प्राप्त मान = 9.967*

तालिका सं0 6 में दर्शित ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की आर्थिक वर्गवार राय का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि निम्न आर्थिक स्थिति वाले 48.08% उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण शक्ति संरचना में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है, जबकि इस वर्ग के 30.77% उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण शक्ति संरचना में सामान्य तथा 21.15% उत्तरदाताओं के अनुसार बहुत कम परिवर्तन हुआ है। वहीं मध्यम आय वर्ग के 40% उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण शक्ति संरचना में सामान्य, 31.43% उत्तरदाताओं के अनुसार बहुत अधिक तथा 28.57% उत्तरदाताओं के अनुसार बहुत कम परिवर्तन हुआ है। इसके विपरीत उच्च आयवर्ग के 48.48% उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण शक्ति संरचना में बहुत कम, 30.3% उत्तरदाताओं के अनुसार सामान्य तथा 21.21% उत्तरदाताओं के अनुसार बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है।

तालिका सं0 6 से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण शक्ति संरचना में बहुत कम परिवर्तन होना मानने वालों में सबसे अधिक उत्तरदाता उच्च आयवर्ग (48.48%) से तथा सबसे कम उत्तरदाता निम्न आयवर्ग (21.15%) से हैं। इसके विपरीत बहुत अधिक परिवर्तन होना मानने वाले उत्तरदाताओं में सबसे अधिक उत्तरदाता निम्न आय वर्ग (48.08%) से तथा सबसे कम उत्तरदाता उच्च आय वर्ग (21.21%) के हैं। इस अन्तर का आगणित काई-वर्ग मान 9.967 है, जो स्वतन्त्रता अंश 4 एवं सम्भाव्यता स्तर 0.05 पर तालिका काई-वर्ग मान (9.488) से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की राय में अधिक वर्गवार सार्थक अन्तर है।

तालिका सं0 7: ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन के बारे उत्तरदाताओं की शैक्षिक वर्गवार राय

परिवर्तन की स्थिति	शैक्षिक स्थिति के अनुसार उत्तरदाताओं का विवरण					
	निम्न		मध्यम		उच्च	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
बहुत कम	8	22.22	13	26.53	16	45.71
सामान्य	12	33.33	19	38.78	9	25.71
बहुत अधिक	16	44.44	17	34.69	10	28.57
योग	36	100.00	49	100.00	35	100.00

काई वर्ग का प्राप्त मान = 5.996

तालिका सं0 7 में दर्शित ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की शैक्षिक वर्गवार राय का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि निम्न शैक्षिक स्थिति वाले 44.44% उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण शक्ति संरचना में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है, जबकि इस वर्ग के 33.33% उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण शक्ति संरचना में सामान्य तथा 22.22% उत्तरदाताओं के अनुसार बहुत कम परिवर्तन हुआ है। वहीं मध्यम शैक्षिक स्थिति के 38.78% उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण शक्ति संरचना में सामान्य, 34.69% उत्तरदाताओं के अनुसार बहुत अधिक तथा 26.53% उत्तरदाताओं के अनुसार बहुत कम परिवर्तन हुआ है। इसके विपरीत उच्च शैक्षिक स्थिति के 45.71% उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण शक्ति संरचना में बहुत कम, 28.57% उत्तरदाताओं के अनुसार बहुत अधिक तथा 25.71% उत्तरदाताओं के अनुसार सामान्य परिवर्तन हुआ है।

तालिका सं0 7 से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण शक्ति संरचना में बहुत कम परिवर्तन होना मानने वालों में सबसे अधिक उत्तरदाता उच्च शैक्षिक स्थिति (45.71%) से तथा सबसे कम उत्तरदाता निम्न शैक्षिक स्थिति (22.22%) के हैं। इसके विपरीत बहुत अधिक परिवर्तन होना मानने वाले उत्तरदाताओं में सबसे अधिक उत्तरदाता निम्न शैक्षिक (44.44%) के तथा सबसे कम उत्तरदाता उच्च शैक्षिक स्थिति (28.57%) के हैं। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की राय में शैक्षिक वर्गवार अन्तर है, परन्तु इस अन्तर का आगणित काई-वर्ग मान 5.996 है, जो स्वतन्त्रता अंश 4 एवं सम्भाव्यता स्तर 0.05 पर तालिका काई-वर्ग मान (9.488) से कम है। अतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की शैक्षिक वर्गवार राय में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष निम्नवत् हैं:-

सामाजिक वर्गवार उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता में परिवर्तन की प्रवृत्ति में सार्थक अन्तर है (तालिका काई-वर्ग मान 9.68)। इसका कारण यह है कि सामान्य जाति के लोगों में पूर्व में राजनीतिक सहभागिता की उच्च स्थिति थी, परन्तु नवीन पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत कमजोर सामाजिक वर्ग को मिल रहे अवसरों के कारण उनकी राजनीतिक सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की राय में सामाजिक वर्गवार सार्थक अन्तर है (तालिका काई-वर्ग मान 10.103)। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन तो हुआ है और इस परिवर्तन के फलस्वरूप अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के नये नेतृत्व का उदय भी हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से प्रभुत्वशाली जातियाँ इसे स्वीकार करने पर हिचक रही है।

ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की राय में आर्थिक वर्गवार सार्थक अन्तर भी है (आगणित काई-वर्ग मान 9.967)। आर्थिक वर्गवार उत्तरदाताओं की राय में सार्थक अन्तर होने का कारण यह हो सकता है कि नवीन पंचायती राज व्यवस्था के फलस्वरूप ग्रामीण शक्ति संरचना में जो परिवर्तन हुआ है, वह मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्व में ही अधिक प्रभावी है। इसका ग्रामीण आर्थिक संरचना पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। आर्थिक रूप से सम्पन्न ग्रामीण अभी भी एक शक्ति के रूप में जाने जाते हैं।

ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की राय में शैक्षिक वर्गवार अन्तर तो है, परन्तु यह अन्तर सार्थक नहीं है (अगणित काई-वर्ग मान 5.996)।

अतः यह कहा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन के अंग पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण शक्ति संरचना को निश्चित रूप से परिवर्तित किया है, परन्तु यह परिवर्तन मुख्य रूप से राजनीतिक संरचना का ही हुआ है। सामाजिक एवं आर्थिक संरचना में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अटल, योगेश (1971), लोकल कम्युनिटीज एण्ड नेशनल पालिटिक्स, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।

अवस्थी, ए0 एवं ए0पी0 अवस्थी (2008), भारतीय प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।

आहुजा, राम (2011), भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर।

काला, सुधा (2008), पंचायती राज ग्रामीण विकास का राज, कुरूक्षेत्र, वर्ष-54, अगस्त पृ0 17-20।

कोठारी, रजनी (1970), कास्ट इन इण्डियन पालिटिक्स, ओरिएंट लाँगमैन, नई दिल्ली।

टिंकर ह्यूज (1967), दि फाउण्डेशन आफ लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट इन इण्डिया, पाकिस्तान एण्ड बर्मा, लालवानी पब्लिशर्स, बाम्बे।

नारायन, इकबाल तथा माथुर, एस0डी0 (1969), पंचायतीराज कंसेप्ट एण्ड इंसपाइरेशन, एशिया पब्लिशिंग हाउस बाम्बे।

बेतेई, आन्द्रे (1966), कास्ट, क्लास एण्ड पावर: चेंजिंग पैटर्नस आफ स्ट्रेटीफिकेशन इन ए तंजौर विलेज, आक्सफोर्ड युनीवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

भारत सरकार (1978), अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

भारत सरकार (1986), लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का प्रतिवेदन, पंचायतीराज प्रपत्र, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

भारत सरकार (1987), जी0वी0के0 राव समिति का प्रतिवेदन, प्रकाशन विभाग, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1987।

मुकर्जी, आर0के0 (2006), लोकल गवर्नमेन्ट इन एंशिएंट इण्डिया, सेवेन्थ एडीसन, फस्ट पब्लिश्डि इन 1958, मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली।

मेरिल, एफ0ई0 एण्ड एच0डब्ल्यू0 एलरिज, (1949), कल्चर एण्ड सोसाइटी, प्रेंटिस हाल, न्युयार्क।

रेड्डी, जी0आर0 (1970), पैटर्नसआफ पंचायती राज इन इण्डिया, मैकमिलन, नई दिल्ली।

लवानियाँ, एम0एम0 व शशि के0 जैन (1987), ग्रामीण समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर।

विद्यालंकार, सत्यकेतु (1965), प्राचीन भारत की शासन संस्थाएं और राजनीति विचार, श्रीसरस्वती सदन, दिल्ली।

शर्मा, अशोक (2002), भारत में स्थानीय प्रशासन, आर0बी0एस0ए0 पब्लिशर्स, जयपुर।

सरकार, डी0सी0 (1955), सेलेक्ट इंसक्रिप्शन्स, वियरिंग आन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड सिविलाइजेशन, कलकत्ता।